# उत्तर प्रदेश

# विशिष्ट करेंट अफेयर्स

# नवंबर 2022

## चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर टाइगर रिज़र्व बना भारत का 53वाँ टाइगर रिज़र्व

• उत्तर प्रदेश में एक और टाइगर रिज़र्व रानीपुर टाइगर रिज़र्व भारत का 53वाँ बाघ रिज़र्व बन गया है।उत्तर प्रदेश में यह रिज़र्व चित्रकूट ज़िले के रानीपुर में स्थित है, जो 36 वर्ग किमी. क्षेत्र में फैला है। 230.32 वर्ग किमी. कोर क्षेत्र और 299.05 वर्ग किमी. बफर क्षेत्र वाला यह टाइगर रिज़र्व बाघ संरक्षण की कोशिशों को मजबूत करेगा। इसके अलावा करीब 300 वर्ग किमी. का क्षेत्रफल इसमें और जोड़ा जा रहा है।

• इससे राज्य में बाघों की संख्या में भी वृद्धि होगी, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र में इको पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र का आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विकास होगा तथा इसके अलावा प्राकृतिक वातावरण को बेहतर ढंग से सुरक्षित रखा जा सकेगा। इस टाइगर रिजर्व से बुंदेलखंड में स्थानीय जनता को रोज़गार के नए अवसर भी मिलेंगे।

• उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानीपुर टाइगर रिज़र्व मध्य प्रदेश स्थित पन्ना टाइगर रिज़र्व से महज 150 किमी. की दूरी पर स्थित है। इस रिज़र्व में बाघ, तेंदुआ, भालू, सांभर, चित्तीदार हिरण, चिंकारा और कई पक्षी और सरीसृप पाए जाते हैं।

• विदित है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़ के बाद यह राज्य का चौथा टाइगर रिज़र्व है तथा भारत में बाघों की हालिया गिनती 2018 में की गई थी, जिसके मुताबिक देश में 2967 बाघ हैं और इनमें से 173 उत्तर प्रदेश में हैं।

## गोरखपुर में गोड़धोइया नाला व रामगढ़ ताल का होगा जीर्णोद्धार

• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर विकास परियोजनाओं के अंतर्गत 474.42 करोड़ रुपए की गोड़धोइया नाले और रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार तथा 561.34 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना ज़ोन सी पार्ट-दो, योजनाओं को मंज़ूरी दी।

• गौरतलब है कि गोरखपुर सिटी में गोड़धोइया नाला पहले एक प्राकृतिक नाला था, जिसके आसपास के क्षेत्रों में शहरीकरण के कारण विभिन्न नाले के माध्यम से सीवेज युक्त गंदा पानी गिरने और अतिक्रमण से सिल्ट भर गई है। इसी कारण से यहाँ के आसपास के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

• इसको ध्यान में रखते हुए गोड़धोइया नाला और रामगढ़ ताल के जीर्णोद्धार व इंटरसेप्शन डयवर्जन एवं ट्रीटमेंट की परियोजना तैयार की गई है। परियोजना के अंतर्गत 44300 घरों से निकलने वाले 38 एमएलडी सीवरेज का ट्रीटमेंट किया जाएगा।

• इसमें नाले के दोनों तरफ आरसीसी रिटेनिंग वाल बनाई जाएगी तथा इसके दोनों तरफ सीवरेज लाइन डाली जाएगी। इसके पास में ही सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जाएगा।

• इस परियोजना से गोड़धोइया नाले के 9.7 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले करीब 2.2 लाख परिवारों को बाढ़ और जल जनित बीमारियों से राहत मिलेगी। इसके अलावा वर्ष 2025 की जनसंख्या की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की सुविधा विकसित की जाएगी। इस पर 561.34 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसमें सीवरेज लाइन डालते हुए 43963 घरों में कनेक्शन भी दिया जाएगा।

## सीताकुंड धाम को अयोध्या-चित्रकूट धाम मार्ग से सीधे जोड़ा जाएगा

• उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता संतोष मणि तिवारी ने बताया कि राज्य के सुल्तानपुर में आदिगंगा गोमती तट पर स्थित सीताकुंड घाट को सीधे अयोध्या-प्रयागराज-चित्रकूट धाम मार्ग से जोड़ा जाएगा।

• संतोष मणि तिवारी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग पर जाम को कम करने व यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिये द्वारिकागंज व टाटियानगर से शहर के अंदर आने वाले दो लिंक हाईवे को फोरलेन में तब्दील करने की योजना है। योजना में से द्वारिकागंज से गोलाघाट तक 10 किमी. की दूरी को शामिल किया गया है तथा इसके अलावा टाटियानगर से रतनपुर टेंढुई तक को भी शामिल किया गया है।

• गोलाघाट से द्वारिकागंज तक 10 किमी. दूरी में फोरलेन निर्माण के लिये 50 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है, जिसमें कई पुल व पुलिया को भी शामिल किया गया है ।

• अयोध्या-चित्रकूट धाम मार्ग से सीताकुंड धाम को जोड़ने को लेकर इस लिंक हाईवे फोरलेन का निर्माण होगा। इस मार्ग की चौड़ाई शहर के अंदर 50 फीट और शहर के बाहर सड़क के मध्य से 75 फीट होगी और निर्धारित सीमा के अंदर कब्जेदारों को मुआवज़ा भी नहीं मिलेगा।

• टाटियानगर से टेंढुई तक लगभग तीन किमी. की दूरी के लिये 10 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है। इसमें भी एक पुल और कई पुलिया को शामिल किया गया है। शासन की मांग पर लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड ने स्टीमेट भी तैयार किया है।

## अप्रैल 2023 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में होंगे

• उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (खेल) नवनीत सहगल ने बताया कि देश में अप्रैल 2023 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश में होंगे।

नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन प्रदेश के चार शहरों लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी तथा नोएडा में होगा। इसमें रोईंग, बास्केटबाल, जूडो, कबड्डी, कुश्ती, स्वीमिंग, बॉक्सिंग सहित लगभग 20 खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा।

• इन खेलों में पूरे देश से लगभग 150 यूनिवर्सिटी के करीब 4,500 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स में अंडर-26 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। वूमेन गेम्स पर विशेष फोकस रहेगा।

• नोएडा में कबड्डी, जूडो, आर्चरी तथा फेंसिंग का आयोजन होगा। गोरखपुर में रोईंग और वाराणसी में रेसलिंग, मलखंब तथा योगा से संबंधित खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित कराई जाएंगी। अन्य प्रतियोगिताएँ राजधानी लखनऊ में होंगी।

• अपर मुख्य सचिव खेल नवनीत सहगल के मुताबिक यूनिवर्सिटी गेम्स के आयोजन से विश्वविद्यालयों में खेल का माहौल बनेगा और यहाँ के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी बनने का अवसर मिलेगा। इस प्रकार की प्रतिस्पर्धाओं के आयोजन से प्रदेश में खेल संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा।

• गौरतलब है कि यह आयोजन खेल मंत्रालय से उत्तर प्रदेश को मिल रहा है, ऐसे में भारतीय खेल प्राधिकरण के दिल्ली में स्थित खेलो इंडिया मुख्यालय की भी यूनिवर्सिटी गेम्स में अहम भूमिका रहेगी।

• इससे पहले यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण ओडिशा (2020) और दूसरा संस्करण कर्नाटक (2021) में हो चुका है। कर्नाटक में आयोजित 20 स्पर्धाओं में देश भर से 190 यूनिवर्सिटी के साढ़े चार हज़ार खिलाड़ी शामिल हुए थे।

## उत्तर प्रदेश शुरू करेगा 'लखपति महिला कार्यक्रम'

• मीडिया जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से और सक्षम बनाने के लिये 'लखपति महिला कार्यक्रम' शुरू करने जा रही है, जिसके ज़रिये शुरुआती तीन वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा।

• राज्य में 'लखपति महिला कार्यक्रम'के ज़रिये ऐसे प्रयास किये जाएंगे कि महिलाओं की वार्षिक पारिवारिक आय एक लाख रुपये से अधिक पहुँचाई जा सके। इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है और इस कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र के सामने प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है,जिसको मिशन मोड में लागू कर जल्द ही नतीजे हासिल किये जाने की योजना है।

• लखपति महिला कार्यक्रम'के पहले चरण में 11 ज़िलों में इसकी शुरुआत की जाएगी,जिसमें वाराणसी और प्रयागराज के अलावा अलीगढ़, सुल्तानपुर, बहराइच, बांदा, बस्ती, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, हमीरपुर और सोनभद्र शामिल हैं। इन ज़िलों में चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को चिन्हित किया जाएगा और उन्हें विभिन्न प्रकार की योजनाओं से जोड़कर वार्षिक आय में बढ़ोतरी का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

• इस कार्यक्रम को जल्द से जल्द नतीजे तक पहुँचाने के लिये समय सीमा भी निर्धारित की गई है। इसके तहत ज़िला और विकासखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। 15 नवंबर तक ज़िला और विकासखंड स्तर पर टास्क फोर्स का गठन हो जाएगा और 30 मार्च के बाद इसकी समीक्षा की जाएगी।

• टास्क फोर्स के अध्यक्ष ज़िला स्तर पर वहाँ के ज़िलाधिकारी होंगे, जबकि मुख्य विकास अधिकारी सचिव होंगे। उपायुक्त स्वत: रोज़गार, उपायुक्त मनरेगा इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा कृषि विकास, बागवानी, पंचायती राज, महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, मत्स्य पालन, पशुपालन के सदस्य भी इस टास्क फोर्स में शामिल होंगे।

• इस टास्क फोर्स की कार्य प्रगति की मासिक समीक्षा करनी होगी। टास्क फोर्स का कार्य लखपति महिला एप पर विकास खंड के सभी स्वयं सहायता समूह की सदस्यों की स्वघोषित आय को अपलोड

करने एवं मनरेगा में सम्मिलित निजी एवं सामूहिक आजीविका संवर्धन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करनी होगी।

## लखनऊ, कानपुर नगर एवं वाराणसी के सम्पूर्ण क्षेत्र में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू

• उत्तर प्रदेश डीजीपी मुख्यालय ने लखनऊ, कानपुर नगर और वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के पुनर्गठन को मंज़ूरी दे दी। कानपुर नगर और वाराणसी में एक-एक ज़ोन बढ़ाया गया है, जबकि लखनऊ ग्रामीण के थानों को लखनऊ में समायोजित कर दिया गया है।

• एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि तीनों ही ज़िलों में कमिश्नरेट के पहले के ढाँचे में बदलाव किया गया है। अब लखनऊ में 52 थाने, 16 सर्किल और पाँच ज़ोन होंगे। कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट में 49 थाने, 14 सर्किल और चार ज़ोन होंगे। वहीं वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में 30 थाने, 9 सर्किल और तीन ज़ोन होंगे।

• कानपुर में सेंट्रल और वाराणसी में गोमती नया ज़ोन बनाया गया है। कानपुर में एक डीसीपी, एक एडीसीपी और चार एसीपी का पद बढ़ाया गया है। इसी तरह वाराणसी में एक डीसीपी, एक एडीसीपी और तीन एसीपी का पद बढ़ा है।

• लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट में कोई नया ज़ोन नहीं बनाया गया है। ग्रामीण के सात थानों को अलग-अलग ज़ोन में शामिल कर दिया गया है। हालाँकि, लखनऊ में तीन एसीपी का पद बढ़ाया गया है।

• वाराणसी में गोमती नया ज़ोन होगा। इसके साथ ही वाराणसी में अब ज़ोन की संख्या दो से बढ़कर तीन हो गई है। सर्किल की संख्या भी छह से बढ़कर नौ हो गई है। काशी ज़ोन में 13 थाने, वरुणा ज़ोन में 10 थाने और गोमती ज़ोन में सात थाने रखे गए हैं। काशी ज़ोन में चार सर्किल, वाराणसी ज़ोन में तीन सर्किल और गोमती ज़ोन में दो सर्किल रहेंगे।

## उत्तर प्रदेश में नई पर्यटन नीति-2022 को मिली मंज़ूरी

• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता से हुई कैबिनेट बैठक में राज्य की नई पर्यटन नीति-2022 को मंज़ूरी मिली।

• राज्य की नई पर्यटन नीति में होटल इंडस्ट्री के लिये निवेश आधारित सब्सिडी की व्यवस्था की गई है। 10 करोड़ रुपए तक के निवेश पर 2 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 40 करोड़ रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। इसमें होटलों को उद्योग का दर्जा मिलेगा तथा पानी, बिजली संपत्ति कर, सीवरेज टैक्स की दरें भी व्यवसायिक की जगह औद्योगिक होंगी।

• नई पर्यटन नीति के अंतर्गत भगवान राम से जुड़े सभी स्थलों को रामायण सर्किट, भगवान कृष्ण से जुड़े धार्मिक स्थलों को कृष्ण सर्किट के तौर पर विकसित किया जाएगा। जिन नए पर्यटन गंतव्यों का विकास किया जाएगा, इसमें रामायण सर्किट प्रमुख होगा।

• रामायण सर्किट में अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर समेत अन्य धार्मिक स्थल शामिल होंगे। इन स्थलों को भगवान राम एवं माता सीता के प्रतीकों के तौर पर देखा जाता है।

• इसी तरह कृष्ण सर्किट में मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगाँव, बलदेव से लेकर अन्य धार्मिक स्थलों को जोड़ा जाएगा तथा बुद्धिस्ट सर्किट में कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कौशांबी, श्रावस्ती, रामग्राम समेत अन्य स्थल शामिल होंगे।

## सोनौली में एयरपोर्ट की तर्ज पर बनेगा लैंडपोर्ट

• उत्तर प्रदेश के महराजगंज ज़िले के डीएम सत्येंद्र कुमार ने बताया कि महराजगंज के बौद्ध सर्किट के अंतर्राष्ट्रीय एक्जिट प्वाइंट सोनौली में एयरपोर्ट की तर्ज पर 120 एकड़ कैंपस में इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट (आईसीपी) लैंडपोर्ट बनेगा।

• सत्येंद्र कुमार ने बताया कि लैंडपोर्ट के लिये भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा हो चुका है। चहारदवारी का निर्माण कार्य चल रहा है। जल्दी ही शिलान्यास के बाद डीपीआर के मुताबिक कार्यदायी संस्था लैंडपोर्ट बनाएगी।

• सोनौली बॉर्डर के समीप बनने जा रहे इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बौद्ध सर्किट का एक महत्त्वपूर्ण निकास बिंदु है। यह गौतम बुद्ध की जन्मस्थली और लोकप्रिय बौद्ध पर्यटन केंद्र लुंबिनी के नज़दीक है। विदेश से आने वाले यात्रियों और पर्यटकों को सोनौली में अत्याधुनिक सुविधाओं का अहसास कराने के मापदंड के आधार पर यह लैंडपोर्ट विकसित किया जाएगा।

• निर्माण के बाद कस्टम, एसएसबी, पुलिस आव्रजन सहित खुफिया एजेंसियों के कार्यालय एक ही कैंपस में रहेंगे। इससे जाँच में सहुलियत मिलेगी तथा नेपाल के साथ व्यापार में तेजी आएगी।

• लैंडपोर्ट में टर्मिनल बिल्डिंग, नेपाल व भारत साइड पार्किंग/बस टर्मिनल, होटल, इंपेक्शन शेड कस्टम, आयात-निर्यात के लिये वेयरहाउस, रेलवे टर्मिनल में आयात-निर्यात के लिये भवन, ट्रक पार्किंग, तोरण, मेंटिनेंस शेड, हैलिपेड, क्वांरटीन ब्लॉक, आइसोलेशन ब्लॉक, वॉच टॉवर व पेट्रोल बंक आदि का निर्माण होगा।

• उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने वर्ष 2004 में इंडो-नेपाल के सोनौली बॉर्डर पर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के निर्माण की मंजूरी दी थी।

## उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में बनेगा डाटा सेंटर

• उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि राज्य के हर ज़िले में व्यूनाऊ इंफोटेक कंपनी द्वारा डाटा सेंटर के लिये इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इस संबंध में राज्य के औद्योगिक विकास आयुक्त अरविंद कुमार और व्यूनाऊ इंफोटेक कंपनी के एमडी सुखविंदर सिंह खरौर ने 13500 करोड़ रुपए के एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं।

• दुर्गा शंकर मिश्र ने बताया कि उत्तर प्रदेश तेज़ी से ग्लोबल डाटा सेंटर ऑपरेटरों के लिये पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में उभर रहा है और एमओयू हस्ताक्षर के बाद राज्य में एज डाटा सेंटर का दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क स्थापित होगा।

• उन्होंने बताया कि राज्य सरकार प्रति व्यक्ति आय को बढ़ावा देने के लिये राज्य में एक विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी बुनियादी ढाँचा तैयार करने के लिये कदम उठा रही है। इसी दिशा में राज्य में डाटा सेंटर स्थापित किये जाएंगे।

• कंपनी के एमडी सुखविंदर सिंह ने बतया कि व्यूनाऊ इंफोटेक कंपनी राज्य के सभी 75 ज़िलों में 750 डाटा सेंटर स्थापित करने के लिये प्रतिबद्ध है। कंपनी द्वारा पहला पायलट डाटा सेंटर मोरटा गाज़ियाबाद में पहले ही चालू कर दिया गया है।

• उल्लेखनीय है कि आईटी विभाग ने अब तक राज्य में कई हाइपरस्केल डाटा सेंटर पार्क और इकाइयाँ स्थापित करने के लिये 75,000 करोड़ रुपए निवेश को आकर्षित किया है, जिनमें से 20,000 करोड़ रुपए जून 2022 में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3.0 के दौरान लॉन्च किये गए थे।

## ‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023’

• नई दिल्ली स्थित सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय भवन में उत्तर प्रदेश को देश के विकास का ग्रोथ इंजन बनाने के संकल्प के साथ राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023’ के आयोजन की औपचारिक घोषणा की।

• मुख्यमंत्री ने ''उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023'' के लोगो का अनावरण भी किया और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश आज एक प्रगतिशील परिवर्तनकारी यात्रा के शिखर पर है।

• प्रधानमंत्री जी द्वारा निर्धारित 'आत्मनिर्भर भारत'का विज़न इस कायाकल्प का प्रमुख स्तंभ है। भारत को +5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का देश बनाने के प्रधानमंत्री जी के विज़न का अनुकरण करते हुए, उत्तर प्रदेश ने अपने लिये +1 ट्रिलियन का लक्ष्य रखा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार 10 से 12 फरवरी, 2023 तक लखनऊ में एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन कर रही है, ताकि राज्य में उपलब्ध असीम व्यावसायिक अवसरों से देश और दुनिया लाभान्वित हो सके।

• मुख्यमंत्री ने बताया कि यह इन्वेस्टर्स समिट वैश्विक औद्योगिक जगत् को आर्थिक विकास में सहयोग करने के लिये एक एकीकृत मंच प्रदान करने में उपयोगी सिद्ध होगी। इस तीनदिवसीय वैश्विक सम्मेलन में विश्व स्तर के नीति-निर्धारकों, कॉर्पोरेट जगत् के शीर्ष नेतृत्व, व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों, एकेडेमिया, विचार मंच एवं प्रबुद्धजनों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा तथा सामूहिक रूप से व्यावसायिक संभावनाओं एवं सहभागिता के अवसरों पर मंथन किया जाएगा।

• उन्होंने बताया कि समिट के भव्य आयोजन में भागीदारी करने के लिये अब तक लगभग 21 देशों ने उत्साह जताया है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, यूनाइटेड किंगडम और मॉरीशस पार्टनर कंट्री के रूप में सहभागिता करेंगे। इसके अलावा, दुनिया भर के औद्योगिक निवेशकों को समिट में आमंत्रित करने के लिये प्रदेश सरकार भी 18 देशों एवं भारत के 7 प्रमुख नगरों में रोड-शो भी आयोजित कर रही है।

• कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ने पिछले कुछ वर्षों में सक्षम नीतिगत समर्थन एवं विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचा प्रदान करके अपने कारोबारी माहौल में बड़े पैमाने पर सुधार किया है। प्रोएक्टिव इनवेस्टर कनेक्ट तथा हैंडहोल्डिंग के लिये समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने एवं उनके कार्यान्वयन की निगरानी के लिये 'निवेश सारथी'नामक एक नई ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है। इसके अलावा एक ऑनलाइन इंसेंटिव मैनेजमेंट सिस्टम भी विकसित किया गया है।

## उत्तर प्रदेश के शहरों में लागू होगा इंदौर का SWM मॉडल

• उत्तर प्रदेश में स्वच्छ, हरित और नियोजित शहरों को सुनिश्चित करने के लिये, राज्य सरकार राज्य के शहरी निकायों में इंदौर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) मॉडल को लागू करेगी।

• देश के सबसे स्वच्छ शहर माने जाने वाले इंदौर के स्वच्छता मॉडल की व्यापक समीक्षा के लिये उत्तर प्रदेश की एक टीम ने हाल ही में अपने दो दिवसीय दौरे के दौरान इंदौर शहर की रणनीति का आकलन किया और ट्रेंचिंग ग्राउंड में स्थित एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का अवलोकन भी किया।

• उत्तर प्रदेश में स्वच्छ भारत मिशन की निदेशक नेहा शर्मा सहित मथुरा-वृंदावन, झाँसी, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, फर्रुखाबाद, कुशीनगर, इकदिल नगर, मुरादाबाद, गोरखपुर जैसे नगरीय निकायों के करीब 13 प्रतिनिधि दौरे पर गए थे।

• उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को इंदौर शहर में स्पॉट फाइन और कचरा संग्रहण शुल्क के बारे में जानकारी दी गई। यात्रा के दौरान पिछले छह वर्षों में स्वच्छता के लिये की गई पहलों पर एक प्रस्तुति दी गई।

• इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के साथ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के अध्यक्ष आदर्श गोयल और दो अन्य सदस्यों ने भी ट्रेंचिंग ग्राउंड स्थित बायो सीएनजी प्लांट का दौरा किया और प्लांट की कार्यप्रणाली को समझा।

• उत्तर प्रदेश के शहरों में नगर निकायों के माध्यम से 300 टन से 400 टन गीले कचरे से बायो सीएनजी प्लांट तैयार करने की योजना है।

## गोरखपुर विश्वविद्यालय में स्थापित होगा इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर

• हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. राजेश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में बताया गया कि गोरखपुर के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोरिटियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर (जीसीआईएआर) स्थापित होगा।

• गोरखपुर के कृषि एवं प्राकृतिक विज्ञान संस्थान में कंसोरिटियम ऑफ इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर (जीसीआईएआर) स्थापित होने से पूर्वांचल में गेहूँ, मक्का एवं धान की उन्नत किस्म के बीजों का विकास होगा और साथ ही विद्यार्थियों को शोध क्षेत्र में व्यापक अनुभव होगा।

• कुलपति प्रो. राजेश सिंह ने बताया कि रिसर्च सेंटर में गेहूँ, मक्का एवं धान की प्रगतिशील किस्मों के विकास से किसानों की आय को दोगुना करने में सहयोग मिलेगा।

## मुख्यमंत्री ने रामनगरी अयोध्या में 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया

• उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामनगरी अयोध्या में परंपरागत तरीके से होने वाले 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया। यह मेला 30 नवंबर, 2022 तक चलेगा।

• मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामायण मेले के द्वितीय दिवस के कार्यक्रम पोस्टर (आवरण छवि) का लोकार्पण भी किया।

• भारत के सांस्कृतिक व आध्यात्मिक वैभव की पुनर्स्थापना के लिये उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सदस्यों के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है।

• रामायण मेला समिति के संयोजक आशीष कुमार मिश्र ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस पोस्टर का लोकार्पण किया है, उसमें रामायण मेला में होने वाले द्वितीय दिवस के कार्यक्रम के क्रम में राम बारात आगमन, पाँव पूजन की रस्म, चारों भाइयों का अग्नि का फेरा और सभी वर-वधु का ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त करने की लीला को दर्शाया गया है।

• इस आवरण छवि को उकेरने का कार्य वैष्णवी गुप्ता एवं प्रिया गुप्ता ने किया है। आवरण छवि में भारतीय लोक कला पर आधारित अवध की लोककला को प्रदर्शित किया गया है। इससे पहले पहला पोस्टर श्री राम जन्मभूमि के गर्भगृह से लोकार्पित किया गया था।

• गौरतलब है कि अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत 1982 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। उन्होंने उद्घाटन सत्र में ही राम की पैड़ी प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। पहले रामायण मेला में लगातार चार दिन मंत्रियों ने अलग-अलग विकास योजनाओं का ऐलान किया, जो इस समय की विकास योजनाओं में प्रमुख हैं।

• पहले रामायण मेला में ही परिक्रमा मार्ग को पक्का करवाने, सरयू तट का नया घाट से लेकर गुप्तारघाट तक विस्तार व सांस्कृतिक विकास के लिये राम कथा पार्क के निर्माण की घोषणा कर उन पर काम शुरू किया गया था।

• 1980 के दशक में रामायण मेला का आकर्षण चरम पर रहा। इसी मेला में श्रीलंका, कोरिया, मलेशिया सहित कई देशों की रामलीला का मंचन किया गया, जो विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं।